New water sheds for Anantapur District, A.P. under DDP

*306. SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any request for sanctioning 200 new watersheds projects under Desert Development Programme (DDP) to Anantapur district has been received in the Ministry from the Government of Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHANTA KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir. In March 2002, the Chief Minister of Andhra Pradesh had written to the Union Minister of Rural Development requesting for sanction of 200 new watershed projects under Desert Development Programme (DDP) for Anantapur district.

(c) 110 new watershed projects have been sanctioned to Anantapur district under DDP in June, 2002.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, I am thankful to the hon. Minister for acceding to the request of the Government of Andhra Pradesh for sanction of 110 new watershed projects...

MR. CHAIRMAN:Then there should be no supplementary...

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, I do want to raise my supplementaries.

Anantapur District has been the second lowest rainfall receiving district of our country, next to Rajasthan. I would like to know whether the Government has considered the request of the Government of Andhra Pradesh for sanctioning a special project under the SGSY to cover 10,000 acres in the desert area of the Anantapur District. I would like to know what action has been taken by the Government in this regard.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, 200 प्रोजेक्ट्स राज्य सरकार ने मांगे थे, उनमें से 110 के लिए 33 करोड़ रुपये मंजूरी दे दी गई है। जिसमें भारत सरकार का 24.75 करोड़ रुपया है। वैसे भी आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की सचमुच में विशेष परिस्थिति हैं। इसीलिए एक जगह के 16 ब्लॉक के लिए लगभग 500 प्रोजेक्टस, उसी जिले के इसी कारण से लिए गए हैं।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, the Government of Andhra Pradesh has requested another Rs. 2.7 crores as second instalment towards the Desert Development Programme. I would like to know the response of the Government on this matter.

श्री शांता कुमार: सभापति जी,जहां तक इंस्टालमेंट का सवाल है, इस प्रोजेक्ट में जितनी इंस्टालमेंट राज्यों को हमसे लेनी चाहिए थीं, राज्य नही ले रहे हैं। स्थिति यह है कि कुल मिलाकर 2283 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये है। और उसमें से इस समय तक हमसे राज्यों को 1017 करोड़ क्लेम करना चाहिए था। हम देने को तैयार बैठे हैं लेकिन हमसे लिया केवल 773 करोड़ हैं क्योंकि पिछली किश्त खर्च करने की शर्त पूरी नही हो रही है। हम देना चाहते है लेकिन लेने की शर्तें पूरी न करने के कारण राज्य पूरा नहीं ले पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसा ही प्रश्न आप अपनी सरकार से पूछें कि भारत सरकार पैसा देना चाहती है, आप ले क्यों नहीं रहें?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, an amount of Rs. 20 lakhs is being spent on every watershed project. The programme is spread over a period of four years. I would like to ask the hon. Minister whether the time span of four years is sufficient, and whether the amount will be enhanced as one watershed project covers only 500 hectares.This amount is very meagre and the time span is very high. I would like to ask the hon. Minister whether the Government is thinking in terms of minimising the time-span and enhancing the money. Apart from this, there is another district called Mehboob Nagar in regard to which a similar proposal has been sent to the Government of India. Kindly consider the request of the Government of Andhra Pradesh. Sir, I would like the Minister to answer specifically.

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, इस समय पांच वर्षों में प्रोजेक्ट पूरा होता है , सात किश्तें हम देते हैं और सरकार का यह विचार है कि पांच वर्षों में प्रोजैक्ट पूरा हो जाना चाहिए। बहुत से प्रोजेक्ट पांच वर्षों के अंदर कम्प्लीट हो रहे हैं।

सूरत सुपर ताप बिजलीघर से निकलने वाली राख

*307. **श्री मोती लाल वोरा**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरतगढ सुपर ताप बिजलीघर से प्रतिदिन कितनी राख निकलती है। और वहां अब तक कितनी राख इकट्ठी हो गई है;

(ख) किन- किन अन्य ताप बिजलीघरों से भारी मात्रा में राख निकल रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस राख के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड़) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?